विशेषसन्दर्भ सं. *01/ 2001*

25 मार्च, 2004

[एस. राजेंद्र बाबू, के. जी. बालकृष्णन, पी. वेंकटरामा रेड्डी, बी. एन. श्रीकृष्णा और जी. पी. माथुर, जे. जे.

भारत का संविधान 19५०

अनुच्छेद 246 और अनुसूची VII सूची 1 प्रविष्टि 53 और सूची II प्रविष्टि 25-गुजरात गैस (पारेषण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2001 अधिनियम को अधिनियमितकरने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता-आयोजितः द. प्राकृतिक गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रावधान विधायी क्षमता के बिना हैं और उस सीमा तक अधिनियम संविधान के अधिकार क्षेत्र क्षेत्र से बाहर है।

अनुच्छेद 246 अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 53-"पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद "-"प्राकृतिक गैस "पर कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता-आयोजितः प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस को को "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद"अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है-इसलिए प्राकृतिक गैस और और तरलीकृत प्राकृतिक गैस संघ के विषय हैं और इसलिए प्राकृतिक गैस पर कानून बनाने के लिए लिए क्षमता संघ के पास विशेष विधायी अधिकार हैं।

अनुच्छेद 246 अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 25-"गैस और गैस कार्य"पर कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता-आयोजितः सूची II की प्रविष्टि 25 में केवल विनिर्मितगैस शामिल है न कि प्राकृतिक प्राकृतिक गैस-इसलिए राज्य विधानमंडलों के पास प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है

अनुच्छेद 245 और 246 अनुसूची VII सूची I, II और III आधार और पदार्थ नियम-विधायी शक्ति के वितरण की प्रयोज्यता-निर्धारित करने के लिए परीक्षणः संयोग से संसद राज्य सूची में शामिल विषय पर कटाक्ष कर सकती है-इसके विपरीत, राज्य विधानमंडल भी संघ सूची में किसी विषय के संबंध में ऐसा कर सकता है-यदि संघर्ष का समाधान नहीं किया जा सका, तो केंद्रीय कानून प्रबल होगा-हालांकि, मतभेद को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

शब्द और वाक्यांशः

"गैस और गैसवर्क्स "-जिसका अर्थ है-भारत के संविधान, 1950 के संदर्भ में, अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 25.

"पेट्रोलियम "", प्राकृतिक गैस "और"तरलीकृत प्राकृतिक गैस "-का अर्थ।

संविधान के 143 (1) अनुच्छेद के तहत निम्नलिखितप्रश्न इस न्यायालय को भेजे गए थे

(1) क्या प्राकृतिक गैस (एल. एन. जी.) सहित किसी भी भौतिक रूप में प्राकृतिक गैस सूची । और संघ की प्रविष्टि 53 में विशिष्टएक संघ विषय है अैार संघ के पास प्राकृतिक गैस पर कानून बनाने की विशेष विधायी क्षमता है।

(2) क्या राज्यों के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 25 के तहत प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के विषय पर कानून बनाने की विधायी क्षमता है।

(3) क्या गुजरात राज्य के पास गुजरात गैस (पारेषण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम वितरण) अधिनियम, 2001 को अधिनियमित्करने की विधायी क्षमता थी।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

आयोजितः 1. तत्काल मामले में विवाद को केवल इस प्रश्न की जांच करके हल किया जा सकता है कि क्या सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 53 में उल्लिखित अभिव्यक्ति 'पेट्रोलियमऔर 'पेट्रोलियम उत्पाद'या 'खनिज तेल संसाधन'प्राकृतिक गैस या उसके व्युत्पन्न रूपों को अपनी दिशा में ले जाएगा।

प्रश्न सं। 1

2.1 . "प्राकृतिक गैस "को पृथ्वी की सतह के नीचे छिद्रपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाये जाने वाले हाइड्रोकार्बन और गैर-हाइड्रोकार्बन गैसों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अक्सर पेट्रोलियम के सहयोग से मिलकर होता है।

किर्कओथोमरः रासायनिक प्रौद्योगिकी का विश्वकोश, तीसरा संस्करण। खण्ड. 11 पेज 630 , संदर्भित संदर्भित किया गया।

2.2 . प्राकृतिक गैस पृथ्वी के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो तलछटी चट्टानों से ढकें होते हैं। इन तलछटों में जैविक स्रोत पदार्थ होते हैं जिनसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता जाता था।

2.3 . विशाल भूमिगत गुफाओं में गैस और तेल पाए जाते हैं। वे दोनों बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसी चट्टानों के सूक्ष्म छिद्रों में पाए जाते हैं। वे आसपास की चट्टान संरचनाओं द्वारा जो रिसाव के लिए अभेद्य हैं, के भारी दबाव में पकड़ लिये जाते हैं। अंततः वे तब मुक्त होते हैं,जब पृथ्वी की सतह खिसकने से कैप चट``टानों में दरार आ जाती है।

3.1 . पेट्रोलियम एक तैलीय, ज्वलनशील तरल है जो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन-केवल हाइड्रोजन और कार्बन वाले यौगिक से बना होता है। पेट्रोलियम में हाइड्रोजन की मात्रा 50 प्रतिशत से 98 प्रतिशत

तक होती है। शेष मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिकों से बना होता है।

द न्यू पॉप्युलर साइंस वॉल्यूम। 2 , संदर्भित किया गया।

3.2 . प्राकृतिक गैस को "एक वाष्प के रूप में खनिज"के रूप में भी परिभाषित किया गया है। । मिश्रण में हाइड्रोकार्बन की विशेषता वाली एक गैस, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परत में पायी जाती है, जिसे ड्रिलिंगद्वारा प्राप्त किया जाता है, और जिसे गर्म करने, रोशनी और अन्य उद्देश्यों उपयोग के लिए शहरों और गांवों, औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों में भेजा जाता है।

कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेडबनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1962] सप. 3 एस. सी. आर. आर. 1, लागू नहीं होता।

बोरिस बनाम कैनेडियन पैसिफिकरेलवे कं., (1953) 1 सभी ई. आर. 451, संदर्भित

वेबस्टर्स न्यू 20 सेंचुरी डिक्शनरी, बिना संक्षिप्त द्वितीय संस्करण और

बैलेनटाइन लॉ डिक्शनरी, तीसरा संस्करण, 1969 , संदर्भित किया गया।

4.1 . पेट्रोलियम के क्षेत्र को शामिल करने वाले विभिन्नकानूनों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उत्पाद, या तो 'पेट्रोलियम'या 'पेट्रोलियम उत्पाद'शब्द को समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है, है, ताकि प्राकृतिक गैस को शामिल किया जा सके।

4.2 . 'पेट्रोलियम'शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'चट्टान का तेल'। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द पेट्रा-ओलियम से हुई है, (पेट्रा-का अर्थ चट्टान या पत्थर और ओलियमका अर्थ तेल है)। इस प्रकार, प्राकृतिक गैस को 'पेट्रोलियम'या 'पेट्रोलियम उत्पाद'अभिव्यक्ति के अंदर अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 15 वीं संस्करण। खण्ड. 19 पी। 589 (1990) , संदर्भित

5. संविधान में उपयोग किए गए विभिन्नशब्दों की व्याख्या करने में विधायी प्रथा पर विचार करना करना महत्वपूर्ण है।

मद्रास राज्य बनाम गैनन डुंकनली एंड कंपनी, [1959] एस. सी. आर. 379 पर निर्भर था।

क्रॉफ्ट वी. डंपी, (1933) ए. सी. 156, उद्धृत।

6.1 . सूची I की प्रविष्टि 53 के तहत, संसद को कानून द्वारा खतरनाक रूप से ज्वलनशील घोषित तेल क्षेत्रों, खनिज तेल संसाधनों, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, अन्य तरल पदार्थों और पदार्थों के विनियमन और विकास के लिए कानून बनाने की शक्ति मिली है। तेल कुऔं से निकाले गए प्राकृतिक उत्पाद में मुख्य रूप से मीथेन शामिल है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन से स्वतंत्र नहीं है; हालांकि कुछ कुऔं से केवल प्राकृतिक गैस ही निकलेगी, अन्य उत्पाद पृथ्वी के भूमिगत कक्षों से निकल सकते हैं। लेकिन सभी तेल क्षेत्रों में संभावित हाइड्रोकार्बन की खोज की जा रही है। इसलिए तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों के विनियमन में

में आवश्यक रूप से प्राकृतिक गैस के विनियमन के साथ-साथ विकास भी शामिल है। देश भर में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का मुक्त औार सुचारू प्रवाह के लिए प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

6.2 . प्राकृतिक गैस में पूरे देश के लोगों की हिस्सेदारी है और इसका लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए। राष्ट्रीय विकास के लिए प्राकृतिक गैस का उचित और उचित उपयोग होना चाहिए। यदि अकेले अकेले एक राज्य को प्राकृतिक गैस निकालने और उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो अन्य राज्य अपने समान हिस्से से वंचित हो जाएंगे। यह स्थिति संघ द्वारा अपनाए गए रुख को मजबूत करती है और इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि "प्राकृतिक गैस"को सूची 1 की प्रविष्टि 53 में शामिल किया गया है। इस प्रकार, विधायी इतिहास और "पेट्रोलियम", "पेट्रोलियम उत्पादों"और "खनिज तेल संसाधनों"की परिभाषा विभिन्न कानूनों और पुस्तकों में निहित है और प्राकृतिक गैस के समान वितरण में शामिल राष्ट्रीय हित, इन सभी कारकों से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि कच्चे और तरलीकृत रूप में "प्राकृतिक गैस"पेट्रोलियम उत्पाद है और खनिज तेल संसाधन का हिस्सा है, जिसे संघ द्वारा विनियमितकरने की आवश्यकता है।

रीः कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, [1993] सप. 1 एस. सी. सी. 96, पर आश्रित पर।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल. एन. जी.) सहित प्राकृतिक गैस एक संघ का विषय है जो सूची । की प्रविष्टि 53 में शामिल है और संघ के पास प्राकृतिक गैस पर कानून बनाने की विशेष विधायी क्षमता क्षमता है।

प्रश्न सं। 2 .

8. गुजरात गैस (पारेषण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 (छ) में दी गई परिभाषा के अनुसार "गैस"को "गैसीय अवस्था का एक मामला जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है"के रूप में परिभाषित किया गया है, इसमें निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस भी शामिल होगी। सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 25 सूची 2 के तहत, राज्य केवल गैस और गैस कार्य के संबंध में कानून पारित करने में सक्षम होगा और "गैस और गैस कार्य"शब्दों के संयोजन को ध्यान में रखते हुए, इस प्रविष्टि का अर्थ विनिर्मितगैस से संबंधित कोई भी कार्य या उद्योग होगा जिसका उपयोग अक्सर औद्योगिक, चिकित्साया अन्य समान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रविष्टि 25 सूची II को समग्र रूप से पढ़ना होगा। उसमें अभिव्यक्तियों की अलग-अलग व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रविष्टि में 'गैस'शब्द दूसरे शब्दों 'गैसवर्क्स'से रंग लेगा। बैलेन्टाइन लॉ डिक्शनरी में, तीसरा संस्करण, 1969 'गैसवर्क्स'को "कृत्रिम गैस के निर्माण के लिए एक संयंत्र"के रूप में परिभाषित परिभाषित किया गया है। इसी तरह, वेबस्टर के न्यू 20 सेंचुरी डिक्शनरी में, इसे "एक ऐसी स्थापना स्थापना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें हीटिंग और लाइटिंग के लिए गैस व्यवस्था का

निर्माण् होता है। डब्ल्यू. डब्ल्यू. फ्री डिक्शनरी डाट काॅम में 'गैसवर्क्स'को गैस का एक कारखाना, सभी मशीनरी अैार उपकरणों के साथ; एक जगह गैस उत्पन्न होती है, के रूप में समझाया गया है। 'गैसवर्क्स'शब्द का अर्थ इस अर्थ में अच्छी तरह से समझा जाता है कि वह स्थान जहां गैस का निर्माण् होता है। इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल है कि सूची II की प्रविष्टि 25 में गैस में प्राकृतिक गैस शामिल है जो 'गैसवर्क्स'में निर्मित गैस से मौलिक रूप से अलग है। इसलिए इसलिए सूची II की प्रविष्टि 25 में केवल विनिर्मितगैस शामिल है और इसके दायरे में प्राकृतिक गैस गैस शामिल नहीं है। यह राज्यों के इस तर्क को नकार देगा कि केवल उनके पास प्राकृतिक गैस और और तरलीकृत प्राकृतिक गैस से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। । संविधान निर्माताओं की भी यही स्पष्ट मंशा है। यह पठन किसी भी तरह से उस प्रविष्टि को 'बेकार वस्तु'नहीं बनाएगा जैसा कि राज्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी, क्योंकि प्राकृतिक गैस का उद्देश्य कभी भी उस प्रविष्टि के दायरे में आना नहीं था। राज्यों का तर्क स्वीकार करना भी मुश्किल है कि सभी 'गैस'को खतरनाक रूप से ज्वलनशील के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पर पहुंचा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस भी राज्य सूची में शामिल है क्योंकि अंतर गैस की विशेषता विशेषता पर नहीं, बल्कि इसकी उत्पत्ति के तरीके पर आधारित है। सूची II की प्रविष्टि 25 में गैसवर्क्स में निर्मित और उपयोग की जाने वाली गैस शामिल है। इस विशिष्टप्रविष्टि 53 को ध्यान में में रखते हुए, किसी भी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए राज्य विधानमंडल के पास प्राकृतिक गैस के संबंध में कोई कानून पारित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं है।

बैलेन्टाइन लॉ डिक्शनरी तीसरा संस्करण। 1969. वेबस्टर का नया 20वां सेंचुरी डिक्शनरी और डब्ल्यू. डब्ल्यू. फ्री डिक्शनरी डाट कॉम, संदर्भित।

9. इस प्रकार, दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः राज्यों के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 25 के तहत प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के विषय पर कानून बनाने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं है।

प्रश्न सं। 3

10. तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः गुजरात गैस (पारेषण, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2001, जहाँ तक प्राकृतिक गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल. एन. जी.) जी.) से संबंधित प्रावधानों का संबंध है, किसी भी विधायी क्षमता के बिना है और यह अधिनियम उस उस हद तक संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

11. भारत का संविधान सातवी अनुसूची में उल्लिखत विभिन्नविषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल विधानमंडल और संसद द्वारा प्राप्त शक्तियों की रूपरेखा को चित्रित करता है।

शक्तियों के वितरण से संबंधित नियमों को भाग 11 में निहित विभिन्नप्रावधानों और अनुसूची की तीन सूचियों में उल्लिखित विधायी प्रमुखों से एकत्र किया जाना है। संघ और राज्य दोनों विधानमंडलों

विधानमंडलों की विधायी शक्ति सटीक शब्दों में दी गई है। सूचियों में प्रविष्टियाँ स्वयं विधान की शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि विधान के क्षेत्र हैं। हालांकि, एक सूची में एक प्रविष्टि की इतनी व्याख्या नहीं की जा सकती है कि वह किसी अन्य प्रविष्टि को रद`द या मिटा दे या किसी अन्य प्रविष्टि को अर्थहीन बना दें। प्रत्यक्ष संघर्ष के मामले में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह तनाव को ठीक करे और संघर्ष को सुलझा कर संघर्ष से बचे। यदि कोई प्रविष्टि ओवरलैप होती है या किसी अन्य प्रविष्टि के साथ स्पष्ट रूप से संघर्ष में होती है, तो उसे सुसंगत बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

12. हालाँकि संसद किसी भी प्रविष्टि पर कानून नहीं बना सकती है, लेकिन व संघ सूची में प्रविष्टि के के दायरे में आने वाले विषय से निपटने के दौरान संयोगवश हस्तक्षेप कर सकती है। इसके विपरीत, विपरीत, राज्य विधानमंडल भी विधान बनाते समय संयोग से संघ सूची में शामिल विषय पर हस्तक्षेप हस्तक्षेप कर सकता है। इस तरह किसी भी स्थिति में आकस्मिक अतिक्रमण को कानून को संविधान संविधान के अधिकार से बाहर होने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी कानून की प्रकृति और सामग्री का पता लगाने के लिए पिथ और पदार्थ के सिद्धांत का आह्वान किया जाता है। हालाँकि, जब जब दोनों विधानों के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है, तो केंद्रीय विधान प्रबल होगा। हालांकि, हर प्रयास संघर्ष को शांत करने के लिए किया जाएगा।

मध्य प्रांत और बरार अधिनियम सं XIV 1938 1939 ई. एल. आर. 18 का, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड़ खुलना, (1947) 74 आई. ए. 23 और सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम मुत्तुस्वामी गौंडर, (1940) एफसीआर 188, पर भरोसा किया।

सलाहकार न्यायनिर्णयः 2001 का विशेष संदर्भ सं. 1।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) 1991 का सं. 852/91, 1991 का सी. ए. सं. 3575,3576।

सोली जे. सोरबजी, महान्यायवादी, रंजीत कुमार, डॉ. ए. एम. सिंघवी, सुश्री. के. अमरेश्वरी, अशोक देसाई, डी. ए. दवे, एस. के. ढोलकिया, बी. सेन, पी. चिदंबरम, फोरोज़ बी. अंधारुजिना, के. सी. कौशिक, प्रतिश कपूर, पी. परमेस्वरन, मनीष सिंघवी, बी. वी. बलराम दास, सुश्री कृष्णा सरमा, जे. आर. लुवांग, सुश्री आशा जी. नायर, अनीश दयाल। वी. सिद्धार्थन, अनिल श्रीवास्तव, गुंटूर प्रभाकर, टी. वी. रत्नम, बी. बी. सिंह एस. एन. शेलट, एड. गुजरात राज्य की जनरल सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, सुश्री सुमिता हजारिका, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री ए. सुभाशिनी, प्रवीण कुमार राय, विनय कुमार गर्ग, गर्ग, अनिल कुमार झा, सुश्री अलका झा, अनीस सुहरावर्दी, के. आर. शशिप्रभु संजय आर. हेगड़े, के. एच. नोबिन सिंह एम. गिरीश कुमार, साकेश कुमार, एस. के. अग्निहोत्री, रवींद्र के.

अदसुरे, एस. एस. शिंदे मुकेश के. गिरी सुश्री अरुणा गुप्ता, रंजन मुखर्जी, यू. हजारिका, सुश्री वी. डी. खन्ना, राधा श्याम जेना, वी. जी. प्रगसम, जे. के. भाटिया, आर. एस. सूरी, रणजी थॉमस, सुश्री भारती उपाध्याय। ए. के. शुक्ला वी. एन. रघुपति, ए. मरियापुथम, सुश्री अरुणा माथुर, नवीन प्रकाश, गोपाल सिंह पी. एन. रामलिंगम वी. बालाजी, अशोक के. श्रीवास्तव, अभिषेक चौधरी, सुश्री रचना श्रीवास्तव, तारा चंद्र शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, जे. एस. अत्री एडिशनल। एड. हिमाचल प्रदेश के के जनरल मयूर शाह, अरुण के. शर्मा, सुश्री प्रतिभा जैन, सुश्री वंदना शर्मा, नागेंद्र सिंह विश्व पाल सिंह शाहिद रिजवी, मनीष गर्ग, सुश्री अनु बिंद्रा, अंशुल सिंघल सुश्री होमा छेत्री, रुस्तम बी. हातिलखानवाला, जी. के. बंसल और जावेद एम. राव उपस्थित दलों के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय/आदेश उदघोषित किया गया:

केजी बालाकृष्णन, **जे**.वर्तमान संदर्भ याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद *143(1)* के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया एक संदर्भ है । गुजरात राज्य विधायिकाने *"*गुजरात गैस *(*पारेषण, आपूर्ति और वितरणका विनियमन*)* अधिनियम, *2001" (*इसके बाद *"*गुजरात अधिनियम*"*के रूप में संदर्भितकियाजाएगा*)* जाएगा*)* नाम से एक अधिनियमपारित किया, जो *19* दिसंबर *2000* से लागू हुआ। अधिनियमका उद्देश्य आम जनता के हित में गैस के पारेषण, आपूर्ति और वितरणके विनियमनऔर राज्य में गैस उद्योग को बढ़ावा देना है, और उस उद्देश्य के लिए गुजरात गैस नियामक प्राधिकरणकी स्थापना करना और मामलों के लिए प्रदान करना है। उससे जुड़ा हुआ और उसका आनुषंगिकहै। *"*गैस*"*शब्द को गुजरात अधिनियमकी धारा *2(*एच*)* *2(*एच*)* के तहत इस प्रकार परिभाषितकियागया है *:-*

*"*गैस*"*का अर्थ गैसीय अवस्था में एक पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है।*"*

राज्य विधायिकाने संविधानकी सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टिसंख्या *25* के तहत अपनी विधायी क्षमता का पता लगाकर उक्त अधिनियमपारित किया।संसद ने पेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पादों के मामलों मामलों से संबंधितसूची *I* की प्रविष्टिसंख्या *53* के तहत विभिन्नअधिनियमपारित किएहैं। सातवीं अनुसूची की अनुसूची की सूची *I* की प्रविष्टिसंख्या *53* इस प्रकार है*: -*

*"*तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों का विनियमनऔर विकास पेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पाद*;* अन्य तरल पदार्थ और पदार्थ जो संसद द्वारा कानून द्वारा खतरनाक रूप से ज्वलनशील घोषितकिएगए हैं।*"*

सूची *II* की प्रविष्टिसंख्या *25* इस प्रकार है*: - "*गैस और गैस कार्य*"*

संविधानका अनुच्छेद *246* यह सिद्धांतदेता है किसातवीं अनुसूची की सूची *I* में उल्लिखितकिसीभी मामले के के संबंध में कानून बनाने की विशेषशक्ति केवल संसद के पास है। जहां तक सूची *II* में प्रविष्टियोंका संबंध है, राज्य की विधायिकाके पास कानूनों को अनुच्छेद *246* के खंड *(i)* और *(ii)* के अधीन बनाने की विशेषशक्ति है। है। अनुच्छेद *246* इस प्रकार है*: -*

"246. संसद और राज्यों के विधानमंडलद्वारा बनाए गए कानूनों की विषयवस्तु*:*

(1) खंड *(2)* और *(3)* में किसीभी बात के बावजूद, संसद के पास सातवीं अनुसूची *(*इस संविधानमें *"*संघ सूची*"*के रूप में संदर्भित*)* में सूचीबद्ध किसीभी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेषशक्ति है। *;*

(2) खंड *(3)* में किसीबात के बावजूद, संसद और, खंड *(1)* के अधीन, किसीभी राज्य के विधानमंडलको भी सातवीं अनुसूची में सूची *III* में सूचीबद्ध किसीभी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। इस संविधान में इसे *"*समवर्ती सूची*"*कहा गया है*)*।

(3) खंड *(1)* और *(2)* के अधीन। किसीभी राज्य के विधानमंडलके पास सातवीं अनुसूची *(*इस संविधानमें *"*राज्य सूची*"*के रूप में संदर्भित*)* में सूचीबद्ध किसीभी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसीहिस्से पर कानून बनाने की विशेषशक्ति है।

(4) संसद को भारत के किसीभी हिस्से के लिएकिसीभी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो *[*किसी *[*किसीराज्य में*]* शामिलनहीं है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में शामिलहो।*"*

जब गुजरात राज्य ने गुजरात अधिनियमपारित किया*)* तो यह प्रश्न जाग्रत हुआ किक्या राज्य सरकार सातवीं सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि*25* के आधार पर विधायीक्षमता के आधार पर सभी रूपों में प्राकृतिक गैस सहित गैस के संबंध में एक अधिनियमपारित कर सकती है। संघीय विधानमंडलने पेट्रोलियमअधिनियम अधिनियम, *1934* पारित किया।भारत संघ ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्नकानून बनाए, अर्थात्, तेल तेल क्षेत्र *(*विनियमनऔर विकास*)* अधिनियम, *1948;* तेल उद्योग *(*विकास*)* अधिनियम, *1974;* पेट्रोलियमऔर और खनिज पाइपलाइन *(* भूमिमें उपयोगकर्ता के अधिकारका अधिग्रहण*)* अधिनियम, *1962;* तेल उद्योग *(*विकास*)* अधिनियम, *1974* ये सभी कानून सातवीं अनुसूची की सूची *I* की प्रविष्टि*53* के तहत विधायीक्षमता क्षमता के आधार पर भारत संघ द्वारा पारित किएगए हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमत में वृद्धिकी। गुजरात के प्राकृतिक गैस उपभोक्ता उद्योगों के संघ और अन्य ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष सिविलरिट याचिकादायर की जिसमें उन्होंने *"*गैस और गैस कार्यों*"*पर कानून बनाने की संघ की विधायीक्षमता को चुनौती दी। इसलिए यह सवाल उठा किक्या *"*प्राकृतिक गैस*"*एक संघ का विषयहै या राज्य का विषयहै और क्या गुजरात राज्य और अन्य राज्यों के पास *"*प्राकृतिक गैस*"*के विषय पर कानून बनाने की विधायीक्षमता है। इस पृष्ठभूमि में, भारत के संविधानके अनुच्छेद *143* के खंड *1* के तहत निम्नलिखितप्रश्न इस न्यायालय को भेजे गए।

(1) क्या तरलीकृत प्राकृतिक गैस *(*एलएनजी*)* सहित किसीभी भौतिक रूप में प्राकृतिक गैस सूची *I* की प्रविष्टि *53* में शामिलएक संघ का विषयहै और संघ के पास प्राकृतिक गैस पर कानून बनाने की विशेषविधायीक्षमता है क्षमता है *?*

(2) क्या राज्यों के पास संविधानकी सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि*25* के तहत प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के विषयपर कानून बनाने की विधायीक्षमता है *?*

(3) क्या गुजरात राज्य के पास गुजरात गैस *(*पारेषण, आपूर्ति और वितरणका विनियमन*)* अधिनियम*2001* को अधिनियमित*/*करने की विधायीक्षमता थी *?*

संदर्भ की प्राप्ति के बाद, राज्यों और केंद्र शासितप्रदेशों को नोटिस जारी कियेगए। भारत के विद्वानअटॉर्नी जनरल भारत संघ की ओर से उपस्थित हुए और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्वविभिन्नवकीलों के माध्यम से कियागया। हमने भारत के विद्वानअटॉर्नी जनरल और विभिन्नराज्यों और केंद्र शासितप्रदेशों की ओर से पेश पेश हुए विद्वानवरिष्ठ वकील को सुना।

विद्वानअटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया किविभिन्नअधिनियमोंमें विभिन्नपरिभाषाएँ इंगितकरती हैं कि'पेट्रोलियम 'पेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पाद'में 'प्राकृतिक गैस'शामिलहै और यह अभिकथितकियागया था कि'प्राकृतिक 'प्राकृतिक गैस'सूची *I* की प्रविष्टि*53* द्वारा आच्छादित कियागया एक संघ विषयहै। यह तर्क दिया गया था कि केंद्र सरकार ने 'पेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पाद'और 'खनिज संसाधन', अर्थात् तेल क्षेत्र *(*विनियमनऔर विकास*)* अधिनियम, *1948* के संबंध में विभिन्नकानून पारित किए तेल उद्योग *(*विकास*)* अधिनियम, *1974; 1974;* पेट्रोलियमऔर खनिज पाइपलाइन *(*भूमिमें उपयोगकर्ता के अधिकारका अधिग्रहण*)*, अधिनियम, *1962; 1962;* और पेट्रोलियमऔर प्राकृतिक गैस नियम, *1959,* उद्योग *(*विकासऔर विनियमन*)* अधिनियम, *1951, 1951,* क्योंकिसातवीं अनुसूची की सूची *1,* प्रविष्टि*53* के तहत अकेले संसद ही ऐसा करने में सक्षम है। अटॉर्नी जनरल द्वारा यह तर्क दिया गया किविभिन्नपरिभाषाएँ इंगितकरती हैं किएक समान और सुसंगत विधायी प्रथा है और यह स्पष्ट है कि"पेट्रोलियमऔर खनिज"शब्दों में प्राकृतिक गैस शामिलहै। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, पारेषण और वितरणमें संतुलितविकाससुनिश्चित करने का कार्य कियाहै और प्राकृतिक गैस एक 'पेट्रोलियमउत्पाद है जो विशेषरूप से केंद्रीय कानून के क्षेत्र में आता है। तरलीकृत प्राकृतिक प्राकृतिक गैस *(*एलएनजी*)* सहित किसीभी भौतिक रूप में 'प्राकृतिक गैस'एक संघ का विषयहै जो सूची *I* की प्रविष्टि*53* के अंतर्गत आता है और सातवीं अनुसूची की सूची *II* के अंतर्गत प्रविष्टि*25* "गैस और गैस कार्यों"से संबंधितहै और यह संबंधितहै सिंथेटिकगैस का निर्माण. प्रारंभ में निर्मितगैस का उपयोग स्ट्रीट लैंप और ऐसे ऐसे अन्य संबद्ध उद्देश्यों को जलाने के लिएकियाजाता था। एसिटिलीन, ऑक्सीजन, कार्बन-डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें स्थानीय रूप से निर्मितऔर उद्योगों में उपयोग की जाती हैं जैसे वेल्डिंग उद्देश्यों के लिए या अस्पतालों में, या वातित पेय तैयार करने आदि के लिएऔर सूची *II* के तहत प्रविष्टि*25* राज्य सरकार को विनियमित*/*और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। स्थानीय उद्योग और खनिज तेल संसाधनों या पेट्रोलियम पेट्रोलियमउत्पादों द्वारा इन गैसों का निर्माण और वितरणसूची *II* की प्रविष्टि*25* के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे यह तर्क दिया गया किगुजरात अधिनियमके प्रावधान संघ के लिएआरक्षितक्षेत्र को ख़त्म करना चाहते चाहते हैं। यह प्रस्तुत कियागया था किगुजरात अधिनियमराज्य सरकार को गैस के वितरणऔर पारेषण के व्यवसाय को विनियमित*/*करने का अधिकारप्रदान करता है और उस अधिनियमके प्रावधान, उदाहरण के लिए लिए खनिज तेल क्षेत्रों को संभालने और संबंधितगतिविधियोंमें तेल आदि के लिएड्रिलिंगमें हस्तक्षेप करने का का प्रावधान करते हैं। यह भी बताया गया किउक्त अधिनियमके कुछ अन्य प्रावधान, अन्य बातों के अलावा, गैस के लाइसेंस और वितरणसे संबंधितहैं और ये प्रावधान राज्य की विधायीक्षमता के दायरे से बाहर हैं।

गुजरात राज्य के विद्वानअधिवक्ता, श्री अशोक देसाई ने तर्क दिया किसूची *11* की प्रविष्टि*25* में प्रयुक्त अभिव्यक्ति"गैस"में सभी प्रकार की गैसें शामिलहोंगी और इसलिए "गैस और गैस कार्यों"से संबंधितकोई भी

कानून पूरी तरह से इसके अंतर्गत है। यह भी तर्क प्रस्तुत कियागया किकलकत्ता गैस कंपनी *(*मालिकाना*)* लिमिटेडबनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य , *[1962] (*सप्ल*) 3* एससीआर *1* में, के अंर्तगत इस न्यायालय द्वारा राज्य की विधायीक्षमता तथा दायरे के सम्बंध में सूची *II* की प्रविष्टि*25* पर आधिकारिकतौर पर सुनाया गया और इस न्यायालय ने माना कि"गैस और गैस कार्यों"से संबंधितसंपूर्ण उद्योग का क्षेत्र सूची *II* की प्रविष्टि*25* के अंतर्गत आएगा। आगे यह प्रस्तुत कियागया कितीन सूचियोंमें प्रविष्टियाँकेवल विधायी प्रमुख या कानून के क्षेत्र थीं और उन्होंने उस क्षेत्र का सीमांकन कियाजिस पर उपयुक्त विधानमंडलकाम कर सकता है और प्रविष्टियोंकी भाषा को सबसे व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए। राज्य के विद्वानवकील यह प्रस्तुत कियागया था किजब दो प्रविष्टियोंके बीच संघर्ष होता है, तो न्यायालय को प्रविष्टियोंका समाधान समाधान करना चाहिए और स्पष्ट रूप से विरोधाभासीप्रविष्टियोंमें सामंजस्य स्थापितकरने का प्रयास करना चाहिए और राज्य को कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचितनहीं कियाजाना चाहिए। विद्वानवकील ने दृढ़ता से आग्रह कियाकिराज्य के पास किसीभी भौतिक रूप में 'प्राकृतिक गैस'से निपटने के लिएकानून बनाने बनाने की विशेषशक्तियां हैं, और इसमें तरलीकृत प्राकृतिक गैस *(*एलएनजी*)* भी शामिलहोगी। राज्य के विद्वानवकील ने विस्तारसे तर्क दिया और इस विषयपर विभिन्नप्रकाशनों और शोध पत्रों को हमारे ध्यान में में लाया ताकियह दिखाया जा सके कि'प्राकृतिक गैस'क्या है और इसके व्युत्पन्न रूप क्या हैं।

आगे यह तर्क दिया गया किगुजरात अधिनियममें परिभाषित"गैस"का अर्थ गैसीय अवस्था में पदार्थ है जिसमें जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है और यह 'पेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पादों'के दायरे में नहीं आएगा। यह तर्क दिया गया कि"गैस"को बिना किसीपेट्रोल या पेट्रोलियमउत्पाद के पृथ्वी के कटोरे से निकाला जा सकता है है और विद्वानवकील के अनुसार, यह सूची *II* की प्रविष्टि*25* के तहत राज्य कानून के क्षेत्र में आएगा।

गुजरात राज्य की ओर से की गई तर्क को लगभग सभी राज्यों ने अपनाया है। असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वानवरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत कियाकिसूची *II* की प्रविष्टि*25* स्पष्ट और स्पष्ट है और यह सुझाव देना गलत है कि"गैस और गैस कार्य"केवल निर्मितगैसों या प्राकृतिक गैस के अलावा अन्य गैसों तक सीमित होना चाहिए। यह तर्क दिया गया किविधायीसूचियोंमें प्रविष्टियोंको व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए और प्रविष्टि*25* सूची *II* में योग्यता के शब्दों को जोड़ना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। यह तर्क दिया गया कि वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक भाषा में। "गैस" *(*प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस *(*एलएनजी*)* सहित*)* "पेट्रोलियमया पेट्रोलियमउत्पादों"से काफी अलग है। यह प्रस्तुत कियागया था किअसम असम में कई गैस क्षेत्र, जैसे पिंगरी, थंगाखट, चुबुआ, जोराजन, गैसों को किसीअन्य पदार्थ के साथ मिलकर नहीं निकाला जाता था और यह पेट्रोलियमऔर तेल से अलग है। यह भी बताया गया किहमारे जैसे संघीय ढांचे ढांचे में, गैस जैसा प्राकृतिक संसाधन किसीदेश के आर्थिकअस्तित्व और समृद्धिके लिएमौलिकहै। राज्य और और संघवाद के सिद्धांतोंके अनुरूप, राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अवसर से वंचितनहीं किया जाएगा। यह सर बायरामजी जीजीभाई बनाम बॉम्बे प्रांत *(1939) 3* एफएलजे *(*एचसी*) 25 31* के पर्यवेक्षण पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत कियागया था कियदि संभव हो तो, न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियमकी की धारा *100* में गैर-विवादास्पदखंड पर वापस आने से पहले केंद्रीय और प्रांतीय सूचियोंमें परस्पर विरोधी वस्तुओं का समाधान करना चाहिए, और उस सिद्धांतको लागू करने में न्यायालय सामान्य शब्दों को

प्रतिबंधितकर सकता है। संघीय सूची का ताकिप्रांतीय सूची में निहित किसीविशेषशक्ति को रद्द न कियाजा सके।

कॉमन कैरियर कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वानवरिष्ठ वकील श्री पी.चिदंबरमने तर्क दिया कि"गैस और गैस कार्यों"से जुड़ी कोई भी औद्योगिकगतिविधियांराज्य के लिएफायदेमंद हैं और राज्य को इस विषयपर कानून बनाने की शक्ति दी जानी चाहिए। सूची *II* की प्रविष्टि*25* में उल्लिखितअभिव्यक्ति"गैस"अपने दायरे 'प्राकृतिक गैस'को लेती है जिसे बिजली और पानी के बराबर माना जाता है। यह तर्क दिया गया कि"प्राकृतिक गैस"को पृथ्वी की सतह के नीचे छिद्रपूर्ण भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन और गैर हाइड्रोकार्बन गैसों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिश्रणके रूप में परिभाषितकियागया है और इसकी स्वच्छता, जलने की गुणवत्ता, उपयोग की सुविधा, कम लागत और प्रचुरता के कारण मुख्य रूप से आवासीय, वाणिज्यिकऔर औद्योगिकसेवा में गर्मी के स्रोत के रूप में उपयोग कियाजाता है। दूसरे शब्दों में, 'प्राकृतिक गैस'का व्यापक रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कियाजाता है। यह प्रस्तुत कियागया था किराज्य अकेले संसाधनों का दोहन करने और इसे उपभोक्ताओं को वितरितकरने की स्थिति में होंगे। यह भी तर्क दिया गया कि'प्राकृतिक गैस'को कई व्यापक श्रेणियोंमें वर्गीकृत कियागया है, जैसे *(1)* गीली गैस जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन जैसे संघनित हाइड्रोकार्बन होते हैं*; (2)* दुबली गैस संघनित हाइड्रोकार्बन की अनुपस्थिति को दर्शाती है*; (3)* सूखी गैस जिसकी पानी की मात्रा निर्जलीकरण प्रक्रिया द्वारा कम हो गई है*; (4)* खट्टी गैस में सल्फाइड और अन्य सल्फर यौगिकहोते हैं और *(5)* मीठी गैस हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य सल्फर यौगिकों यौगिकोंकी अनुपस्थिति को दर्शाती है। यह प्रस्तुत कियागया किये प्राकृतिक गैसें किसीभी पेट्रोलियमउत्पाद उत्पाद से जुड़ी नहीं हैं। विद्वानवकील ने तर्क दिया किराज्य को प्राकृतिक गैस के संबंध में कानून पारित करने की विधायीक्षमता प्राप्त है, क्योंकियह पेट्रोलियमउत्पाद नहीं है। गुजरात अधिनियमको पारित करने के के लिएराज्य की विधायीक्षमता से संबंधितमुख्य प्रश्न पर चर्चा करने से पहले, इसके विभिन्नप्रावधानों का एक एक संक्षिप्तसर्वेक्षण प्रासंगिकहो सकता है। अधिनियमका उद्देश्य आम जनता के हित में गैस के पारेषण, आपूर्ति और वितरणका विनियमनप्रदान करना और राज्य में गैस उद्योग को बढ़ावा देना है। धारा *2(*एच*)* के तहत , "गैस"को गैसीय अवस्था में एक पदार्थ के रूप में परिभाषितकियागया है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। धारा *2(*जी*)* के तहत , "वितरण'का अर्थ थोक उपभोक्ता के अलावा किसी अन्य उपभोक्ता को पाइपलाइनों के माध्यम से कम दबाव पर गैस का वितरणहै। "ट्रांसमिशन'को पाइपलाइनों के माध्यम से उच्च उच्च दबाव पर गैस के संचरण के साधन के रूप में परिभाषितकियागया है। अधिनियमके अध्याय *II* में एक अधिकारीको गैस आयुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव है। अधिनियमका अध्याय *III* गुजरात गैस नियामक प्राधिकरणनामक प्राधिकरणकी स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। प्राधिकरणमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिलहोंगे। योग्यताएं और रिक्तियों को भरने का तरीका धारा *8* और *9* के तहत निर्धारित हैं अधिनियमका प्राधिकरणके कार्यों और शक्तियों का उल्लेख अध्याय *IV* में किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य में गैस को बढ़ावा देने के लिएगैस के पारेषण, आपूर्ति और वितरणको विनियमित्करने का कार्य शामिलहै। किसी लाइसेंसधारी को उसके द्वारा धारित लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश। अधिनियमकी धारा *18* के तहत , अधिनियमके तहत किसीभी जांच के प्रयोजनों के लिएप्राधिकरणको को एक सिविलअदालत की शक्तियां दी गई हैं। अधिनियमका अध्याय *VI* विशेषरूप से कहता है किएक

निर्दिष्ट कंपनी और धारा *55* की उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति राज्य में का व्यवसाय नहीं करेगा और यह नियमों के अधीन होगा, यदि कोई हो, एक निर्दिष्ट कंपनी "राज्य में ट्रांसमिशनका व्यवसाय करेगी। धारा *25(2)* कहती है किकोई भी व्यक्ति राज्य में वितरणके लिएपाइपलाइन पाइपलाइन तब तक नहीं बिछाएगा जब तक किवह लाइसेंसधारी न हो। अधिनियमका अध्याय *IX* अपराध और दंड से संबंधितहै और धारा *34(1)* और *(2)* में कहा गया है किजो कोई भी धारा *23* की उपधारा *(1)* के खंड *(ए)* या उपधारा *(2)* के खंड *(ए)* या *(*बी*)* के उल्लंघन में ट्रांसमिशनका व्यवसाय करता है। धारा *55* या जो कोई धारा *25* का उल्लंघन करके बिना लाइसेंस के वितरणका व्यवसाय करता है या ऐसे वितरणके लिएपाइपलाइन पाइपलाइन बिछाता है , दोषी पाए जाने पर कारावास से दंडितकियाजाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या पांच लाख रुपये से अधिकका जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है या दोनों के साथ और जारी अपराध के मामले में, पहले दिन के बाद हर दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माना बीस हजार रुपये से अधिकनहीं होगा।

पूर्व-संवैधानिक कानूनों के अलावा, संघ ने पेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पादों से संबंधितकई कानून पारित किए किएहैं। खान अधिनियम, *1952;* खान और खनिज *(*विकास*)* अधिनियम, *1957;* तेल क्षेत्र *(*विनियमनऔर विकास*)* अधिनियम , *1948;* पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन *(* भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण*)* अधिनियम, *1962;* तेल उद्योग *(*विकास*)* अधिनियम, *1974;* उद्योग *(*विकासऔर विनियमन*)* अधिनियम, *1957;* पेट्रोलियमऔर प्राकृतिक गैस नियम, *1959* केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कुछ कानून हैं।

भारत का संविधानसातवीं अनुसूची में उल्लिखितविभिन्नविषयोंके संबंध में राज्य विधानमंडलऔर संसद द्वारा प्राप्त शक्तियों की रूपरेखा को चित्रितकरता है। शक्तियों के वितरणसे संबंधितनियमों को भाग *XI* में निहित विभिन्नप्रावधानों और अनुसूची की तीन सूचियोंमें उल्लिखितविधायीप्रमुखों से इकट्ठा कियाजाना है। जाना है। संघ और राज्य विधानमंडलोंदोनों की विधायी शक्तियाँ सटीक शब्दों में दी गई हैं। सूचियोंमें प्रविष्टियाँस्वयं कानून की शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि कानून के क्षेत्र हैं। हालाँकि, एक सूची में किसीप्रविष्टिकी इतनी व्याख्या नहीं की जा सकती किवह किसीअन्य प्रविष्टिको रद्द या मिटादे या किसीअन्य प्रविष्टिको अर्थहीन बना दे। स्पष्ट विवादके मामले में, यह न्यायालय का कर्तव्य है किवह तनाव को दूर करे और संघर्ष को सुलझाकर संघर्ष से बचें। यदि कोई प्रविष्टिकिसीअन्य प्रविष्टिके साथ ओवरलैप होती है या स्पष्ट रूप से विरोधमें है, तो उसमें सामंजस्य स्थापितकरने का हर संभव प्रयास कियाजाएगा।

जब भारत सरकार अधिनियमकी सूची *I* की प्रविष्टि*45*, उत्पाद शुल्क और सूची *II* की प्रविष्टि*18*, माल की बिक्री पर करों के बीच सामंजस्य स्थापितकरने के बारे में प्रश्न उठा*; 1935*, सर मौरिस ग्वेयर, सी.जे., ने पुनः*: 1938* के मध्य प्रांत और बरार अधिनियमसंख्या *XIV 1939* ईएलआर *18* में पृष्ठ *42-44* पर देखा*:*

"सामान्य शब्दों में शक्ति का अनुदान, अपने आप में, निस्संदेह व्यापक अर्थों में समझा जाएगा, लेकिनयह उसी अधिनियममें अन्य स्पष्ट प्रावधानों, संदर्भ के निहितार्थ और यहां तक किउत्पन्न होने वाले विचारोंसे भी भी योग्य हो सकता है। जो अधिनियमकी सामान्य योजना प्रतीत होती है।"

आगे यह देखा गया*:*

.....इसे हल करने का प्रयास कियाजाना चाहिए, जैसा किन्यायिक समितिने कहा है किअधिनियमके संदर्भ संदर्भ और योजनाओं का सहारा लेकर, और दो स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधीन्यायक्षेत्रों के बीच, दो प्रविष्टियों को एक साथ पढ़कर उनकी व्याख्या करना, और जहां आवश्यक हो, एक की भाषा को दूसरे की भाषा से संशोधितकरके सुलह का प्रयास कियाजाना चाहिये। यदि वास्तव में ऐसा मेल-मिलापअसंभव साबित होता है, है, तभी, और केवल तभी, गैर-अस्थिर खंड प्रभावी होगा और संघीय शक्ति प्रबल होगी।"

हालाँकिसंसद राज्य सूची में किसीभी प्रविष्टिपर कानून नहीं बना सकती है, लेकिनवह संघ सूची में प्रविष्टिके के दायरे में आने वाले विषयसे निपटने के दौरान संयोगवश ऐसा कर सकती है। इसके विपरीत, राज्य विधानमंडलभी कानून बनाते समय संयोगवश संघ सूची में शामिलविषयोंपर ध्यान केंद्रित कर सकता है। किसीभी स्थिति में इस तरह के आकस्मिक अतिक्रमण से कानून को संविधानके दायरे से बाहर होने की आवश्यकता नहीं है। कानून की प्रकृति और सामग्री का पता लगाने के लिएकभी-कभी मज्जा और पदार्थ के सिद्धांतका उपयोग कियाजाता है। हालाँकि, जब दो कानूनों के बीच कोई असंगत टकराव होता है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। हालाँकि, संघर्ष को सुलझाने का हर संभव प्रयास कियाजाएगा।

प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी और अन्य बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड,खुलना, *1947 (74)* आईए *23* में, भारत के के संघीय न्यायालय से एक अपील थी, बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट, *1940* के प्रावधानों की वैधता के संबंध में प्रश्न उठा। प्रतिवादी द्वारा मुख्य विवादइसमें यह था किप्रांतीय विधानमंडलके पास प्रविष्टि*27* सूची *II* – "मनी लैंडिगऔर मनी लैंडर्स "के तहत कोई अधिनियमबनाने की कोई शक्ति नहीं थी - क्योंकियह संयोगवश "प्रॉमिसरीनोट्स"और "बैंकिंग"पर आघात करता है, जो संघीय विधानमंडलके लिएआरक्षितविषयहै। ऐसा देखा देखा गया :

"विभिन्नविधायिकाओंकी शक्तियों के बीच इतनी स्पष्ट कटौती करना संभव नहीं है: वे समय-समय पर ओवरलैप होने के लिएबाध्य हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधानअधिनियमको लागू करते समय ब्रिटिश संसद को ब्रिटिश के कामकाज का एक लंबा अनुभव था उत्तरी अमेरिका अधिनियम और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल अधिनियमऔर यह अवश्य जानते होंगे किव्यवहार में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है किकई विधायिकाओंको सौंपी गई शक्तियाँ कभी भी ओवरलैप नहीं होंगी।"

सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम मुत्तितस्वामीगौंडर, *(1940)* एफसीआर *188* नामक वाद में सर मौरिस ग्वेयर, सीजे की निम्नलिखितटिप्पणियोंको अनुमोदन के साथ उद्धृत कियागया था:

"यह समय-समय पर अनिवार्य रूप से होता है किकानून, हालांकिएक सूची में एक विषयसे निपटने का दावा करता है, दूसरी सूची में एक विषयको भी छूता है, और अधिनियमके विभिन्नप्रावधान इतनी बारीकी से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं किसख्ती से अंध-पालन कियाजा सकता है। मौखिकव्याख्या के परिणामस्वरूप बड़ी बड़ी संख्या में क़ानूनों को अमान्य घोषितकर दिया जाएगा क्योंकिउन्हें लागू करने वाले कानून निषिद्धक्षेत्र में में कानून बनाते प्रतीत हो सकते हैं। इसलिएन्यायिक समितिद्वारा जो नियम विकसितकियागया है, जिससे यह पता लगाने के लिएविवादितक़ानून की जांच की जाती है इसका 'मर्म और सार', या इसकी 'वास्तविक प्रकृति और चरित्र', यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि"क्या यह इस सूची में या उसमें मामलों के संबंध में

कानून है।"उनके आधिपत्यइस बात से सहमत हैं कियह मार्ग उन आधारों का सही वर्णन करता है जिन पर नियम स्थापितहै, और यह भारतीय के साथ-साथ डोमिनियनकानून पर भी लागू होता है।"

गुजरात राज्य के विद्वानअधिवक्तातर्क प्रस्तुत कियाकिसातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि*25* राज्य विधानमंडलको गैस और गैस-कार्यों से संबंधितकिसीभी विषयपर कानून बनाने की शक्ति देती है और कलकत्ता गैस कंपनी लिमिटेडमामक वाद में इस न्यायालय द्वारा इस पर विचारकियागया था और राज्य विधायिकाद्वारा पारित अधिनियम, अर्थात् ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, *1960* को संवैधानिक रूप से वैध वैध माना गया था। मामले के संक्षिप्ततथ्य इस प्रकार हैं*:* ओरिएंटल गैस कंपनी इंग्लैंड में पंजीकृत थी। इसे कलकत्ता और उसके उपनगरों में पाइप बिछाने और उक्त उद्देश्य के लिएसड़कों की खुदाई करने का अधिकार दिया गया था। भारत में कारोबार करने वाली एक फर्म ने उक्त ओरिएंटल गैस कंपनी के *98* प्रतिशत शेयर खरीदे और कलकत्ता गैस कंपनी लिमिटेडनाम से एक सीमितदेयता कंपनी शुरू की। एक समझौते के द्वारा कलकत्ता गैस कंपनी को ओरिएंटल गैस कंपनी का प्रबंधक नियुक्त कियागया। पश्चिम बंगाल विधानमंडलने एक अधिनियमपारित कियाजिसके तहत राज्य सरकार ने ओरिएंटल गैस कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण पांच साल की अवधि के लिए अपने हाथ में ले लिया। अपीलकर्ता कलकत्ता गैस कंपनी लिमिटेडने उक्त अधिनियमकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए संविधानके अनुच्छेद *226* के तहत एक याचिकादायर की की । राज्य सरकार ने तर्क दिया किसूची *II* की प्रविष्टि*25* के आधार पर, पश्चिम बंगाल विधानमंडलगैस उद्योग को प्रभावितकरने वाले कानून बनाने में सक्षम है। बेंच के लिए सुब्बा राव, जे., जैसा किवह तत्कालीन समय में, ने इस प्रकार कहा कि

"सूची *II* में प्रविष्टि*24* अपने व्यापक आयाम में गैस और गैस-कार्यों सहित सभी उद्योगों को शामिलकरती है। इसी तरह, उक्त सूची की प्रविष्टि*25* में गैस उद्योग शामिलहै। इसलिए दोनों प्रविष्टियोंके बीच एक स्पष्ट विरोधाभासहै और वे एक-दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ऐसी आकस्मिकता में, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतको लागू कियाजाना चाहिए... यदि प्रविष्टि*24* में उद्योग को गैस और गैस-कार्यों को शामिलकरने के लिएव्याख्या की जाती है, तो प्रविष्टि*25* निरर्थक हो सकती है, और में आगामी प्रविष्टियोंके संदर्भ में, अर्थात् प्रविष्टि*26*, व्यापार और वाणिज्यसे संबंधित, और प्रविष्टि*27*, जो माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरणसे संबंधितहै, इसे इसकी सभी सामग्रियोंसे वंचितकर दिया जाएगा और "बेकार लकड़ी"में बदल दिया जाएगा। यदि औद्योगिक, व्यापार, उत्पादन और आपूर्ति पहलुओं को प्रविष्टि*25* से बाहर कर दिया जाता है, उक्त का आधार गायब हो जाएगा*:* उस स्थिति में हम संविधानके लेखकों की अयोग्यता, सटीकता और तनातनी की की कमी को जिम्मेदार ठहराएंगे।"

हालाँकिकलकत्ता गैस कंपनी के मामले *(*उपरोक्त*)* में यह कहा गया है किसूची *II* की प्रविष्टि*25* के तहत राज्य विधानमंडलको गैस और गैस-कार्यों के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्तियाँ मिलीहैं, लेकिनयह संवैधानिक वैधता का समर्थन करने में कोई सहायता नहीं कर सकता है। गुजरात अधिनियमके तहत 'गैस'शब्द की परिभाषा के रूप में 'गुजरात अधिनियमएक समावेशी परिभाषा है और गैसीय अवस्था में कोई भी पदार्थ जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिलहै, उस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। कलकत्ता गैस कंपनी के मामले में, यह प्रश्न सवाल किक्या *En:ry 25* सूची *II* में उल्लिखित गैस और गैस-कार्य 'पेट्रोलियमया

पेट्रोलियमउत्पाद'अभिव्यक्तिके अंतर्गत आएंगे, सीधे तौर पर शामिलनहीं था और न ही उस मामले में इस पर पर विचारकियागया था।

मौजूदा मामले में विवादको केवल इस सवाल की जांच करके हल कियाजा सकता है किक्या सातवीं अनुसूची की सूची *1* की प्रविष्टि *53* में उल्लिखित अभिव्यक्ति 'पेट्रोलियमऔर 'पेट्रोलियम उत्पाद'या 'खनिज तेल संसाधन'प्राकृतिक गैस को अपने दायरे में ले लेगी। या इसके व्युत्पन्न रूप। इन शर्तों को ठीक से समझकर उपरोक्त प्रश्न पर विचारकियाजा सकता है। दोनों पक्षों के पक्षों ने इस विषयपर विभिन्नआधिकारिकपुस्तकों पुस्तकों के अंश प्रस्तुत किये।

किर्कओथोमर इनसाइक्लोपीडियाऑफ केमिकलटेक्नोलॉजी में, *[*तीसरा संस्करण*]*, वॉल्यूम। *11* पृष्ठ *630*, 'प्राकृतिक गैस'को पृथ्वी की सतह के नीचे छिद्रपूर्ण भूगर्भिकसंरचनाओं में पाए जाने वाले हाइड्रो-कार्बन और गैर-हाइड्रोकार्बन गैसों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिश्रणके रूप में परिभाषितकियागया है, जो अक्सर अक्सर पेट्रोलियमके साथ मिलकरहोता है।

एक विपणनयोग्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए गैस या तेल कुओं से बहने वाली कच्ची प्राकृतिक गैस को जल वाष्प, निष्क्रिय या जहरीले घटकों और संघनित हाइड्रोकार्बन को हटाने के लिएसंसाधितकियाजाना चाहिए। संसाधितगैस मुख्य रूप से मीथेन है, जिसमें थोड़ी मात्रा में ईथेन, प्रोपेन ब्यूटेन, पेंटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। इस गैस को उत्पादक क्षेत्रों से दबाव में भूमिगतपाइपलाइनों के माध्यम से या कम तापमान पर तरलीकृत करके बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और विशेषरूप से डिजाइनकिएगए गए समुद्र में जाने वाले टैंकरों में ले जाया जा सकता है।

प्राकृतिक गैस पृथ्वी के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो तलछटी चट्टानों से ढके होते हैं। ये तलछट पहली बार लगभग *500* मिलियनवर्ष पहले कैंब्रियन काल के दौरान रखी गई थीं, और यह प्रक्रियालगभग *100* मिलियनवर्ष मिलियनवर्ष पहले तृतीयक काल के अंत तक जारी रही। इन तलछटों में कार्बनिक स्रोत सामग्री होती है जिनसे जिनसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियमका उत्पादन कियाजाता था। गैस और पेट्रोलियम, चट्टानों में मौजूद पानी की तुलना में कम घने होने के कारण, अभेद्य चट्टान बाधाओं के नीचे समाहित होने तक ऊपर की ओर पलायन करते हैं।

उपरोक्त विश्वकोशके पृष्ठ *634* पर, प्राकृतिक गैस को रासायनिक संरचना के आधार पर कई व्यापक श्रेणियों वर्गीकृत कियागया है, जो हैं*: (1)* गीली गैस में प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन जैसे संघनित हाइड्रोकार्बन होते हैं*; (2)* दुबली गैस संघनित हाइड्रोकार्बन की अनुपस्थिति को दर्शाती है*; (3)* सूखी गैस एक ऐसी गैस है जिसकी पानी की मात्रा निर्जलीकरण प्रक्रियाद्वारा कम हो गई है*; (4)* खट्टी गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य सल्फर यौगिकहोते हैं*;* और *(5)* मीठी गैस हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य सल्फर यौगिकोंकी अनुपस्थिति को दर्शाती दर्शाती है। जनता को बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस को दुबली, सूखी और मीठी बताया गया है।

कुएं के शीर्ष पर प्राकृतिक गैस की संरचना अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्नहोती है। कई अवांछनीय अवांछनीय घटक मौजूद हो सकते हैं जिन्हें पाइपलाइन में डिलीवरीसे पहले प्रसंस्करण द्वारा हटाया जाना चाहिए।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस *(*एलएनजी*)* के उपयोग में तकनीकी प्रगति ने गैस उद्योग को भंडारण और परिवहन की समस्याओं को हल करने के लिएनए तरीके प्रदान किए।प्राकृतिक गैस को क्रायोजेनिक प्रसंस्करण द्वारा गैसीय अवस्था में व्याप्त मात्रा के *1/600* तक कम कियाजा सकता है, वायुमंडलीय दबाव के पास दोहरी दीवार वाले इंसुलेटेड धातु कंटेनरों में सुरक्षितरूप से संग्रहीत या परिवहन कियाजा सकता है और जब आवश्यक हो, तो पुन: गैसीकृत कियाजा सकता है।

प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य रूप से घरों, वाणिज्यिकभवनों और औद्योगिकप्रसंस्करण के लिएगर्मी प्रदान करने के लिएईंधन के रूप में कियाजाता है।

खंड *17* में पृष्ठ *119* पर, यह कहा गया है कि'पेट्रोलियमशब्द, शाब्दिक रूप से, चट्टानी तेल, पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी स्तर में पाए जाने वाले तैलीय पदार्थ के भंडार के लिएप्रयोग कियाजाता है। पेट्रोलियमका निर्माण पिछलेभूवैज्ञानिक युगों में निर्धारित कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक प्रतिक्रियाओंकी एक जटिल और अधूरी समझी गई श्रृंखला से हुआ था। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बड़े भंडार पाए गए हैं और उनकी रासायनिक संरचना में काफी भिन्नताहै। परिणामस्वरूप, पेट्रोलियमकी किसीएक संरचना को परिभाषितनहीं नहीं कियाजा सकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है किसंरचना अलग-अलग होती है, क्योंकिपौधे, पशु और समुद्री जीवन का स्थानीय वितरणकाफी विविधहै और, संभवत:, पेट्रोलियमअग्रदूतों के गठन के समय भी इसी इसी तरह भिन्नथा।

'द न्यू बुक ऑफ पॉपुलर साइंस'खंड के अनुसार। *2,* पेट्रोलियमएक तैलीय, ज्वलनशील, तरल है जो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन यौगिकोंसे बना होता है जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। पेट्रोलियममें हाइड्रोजन की मात्रा *50* प्रतिशत से *98* प्रतिशत तक होती है। शेष मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिकोंसे बना है। एक व्यापक सिद्धांतके अनुसार, अनगिनतछोटे समुद्री जानवरों और पौधों के अवशेष समुद्र तल पर गिरगए और मिट्टीसे ढक गए। समय के साथ-साथ मिट्टीऔर पौधों तथा जानवरों के के अवशेषों की कई परतें जमा हो गईं। इन तलछटों को अत्यधिकदबाव और गर्मी के अधीन कियागया था, और पृथ्वी की पपड़ी के हिलने पर अक्सर निचोड़ा और विकृतकियागया था। धीरे-धीरे वे तलछटी चट्टान की परतों में परिवर्तित हो गए। उनके भीतर मौजूद पौधे और जानवरों के अवशेष पेट्रोलियमऔर प्राकृतिक गैस में में बदल गए। इस परिवर्तन का विवरणबिल्कुल स्पष्ट नहीं है। विशालभूमिगतगुफाओं में गैस और तेल पाए जाते हैं। वे दोनों बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसी चट्टानों के सूक्ष्म छिद्रों में पाए जाते हैं। वे आस-पास की चट्टानी संरचनाओं द्वारा भारी दबाव में बंधक बनाए जाते हैं जो रिसाव के प्रति अभेद्य होती हैं। अंततः वे मुक्त होते हैं जब पृथ्वी की सतह के खिसकनेसे कैप चट्टान में दरारें पड़ जाती हैं।

'प्राकृतिक गैस'को वेबस्टर के नए *20*वीं सेंचुरी डिक्शनरी संक्षिप्तदूसरे संस्करण में इस प्रकार परिभाषितकिया कियागया है*:*

*"*प्राकृतिक गैस*:* गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, मुख्य रूप से मीथेन, पृथ्वी में कुछ स्थानों पर प्राकृतिक रूप से से पाया जाता है, जहां से इसे ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिएशहरों आदि में पाइप कियाजाता है।*" (*पृ-*756)*

बैलेंटाइन लॉ डिक्शनरी, तीसरा संस्करण, *1969* में, 'प्राकृतिक गैस'को "वाष्प के रूप में एक खनिज"के रूप में परिभाषितकियागया है। मिश्रणमें हाइड्रोकार्बन की विशेषतावाली एक गैस, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परत परत में पाई जाती है, जिसे ड्रिलिंगद्वारा प्राप्त कियाजाता है, और हीटिंग, रोशनी और अन्य उद्देश्यों में के लिएशहरों और गांवों, औद्योगिकऔर वाणिज्यिककेंद्रों में पाइप कियाजाता है।

असम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वानवरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. एएम सिंघवीने बोरिस बनाम कैनेडियन पैसिफिकरेलवे कंपनी और अन्य, *(1953) 1* ऑल ईआर *451* में प्रिवीकाउंसिलके फैसले पर विश्वासव्यक्त किया किया और तर्क दिया कि गैस और पेट्रोलियमदो अलग-अलग वस्तुएं हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां अपीलकर्ता के पास अलबर्टा में एक संपत्तिथी। यह संपत्तिउनके पूर्ववर्तियों द्वारा कैनेडियनपैसिफिकरेलवे कंपनी *(*सीपीआर*)* से अर्जित की गई थी। मूल हस्तांतरण में, सीपीआर ने सभी कोयला, पेट्रोलियमऔर मूल्यवान पत्थर को अपने लिएआरक्षितकर लियाऔर इस आरक्षण के आधार पर, उन्होंने दूसरे प्रतिवादी को को सभी पेट्रोलियमको पट्टे पर दे दिया, जो जमीन के भीतर या नीचे पाया जा सकता है, साथ में काम करने का विशेषअधिकारभी। , नवीनीकरण के अधिकारके अधीन, इसे जीतें और दस साल की अवधिके लिएअपने अपने साथ रखें। वास्तव में, अपीलकर्ता की संपत्तिऔर उसके आसपास की भूमिके नीचे, पेट्रोलियमका एक बड़ा भंडार था जो /छिद्रदार चट्टान के बिस्तर में पाया गया था। इस तल में सबसे नीचे पानी, फिरपेट्रोलियम और ऊपर गैस की परत थी। छिद्रपूर्ण चट्टान और अन्य पदार्थों को एक कंटेनर में रखा गया था, जो अभेद्य और उन्हें आसपास की भूमिसे बंद कर देता था जो इसके बाहर थी, लेकिनकंटेनर के भीतर वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, और, इसलिए पानी की निकासी किसीभी तरह से हो सकती थी। कंटेनर के एक हिस्से से निकलने वाले पेट्रोलियमया गैस के परिणामस्वरूप आम तौर पर खाली जगह उन तीन पदार्थों में से किसीएक से भर जाती है। अपीलकर्ता ने जिस विशेषपदार्थ के मालिकहोने का दावा कियाहै, और जिस हस्तक्षेप पर उसने आपत्तिजताई है, वह पेट्रोलियमके शीर्ष पर स्थित एक टोपी में निहित गैस थी और साथ ही ही कोई भी गैस जो उसकी भूमिके नीचे पेट्रोलियममें घोल में थी या हो सकती है उसकी भूमिके नीचे से निकाला गया। इसलिए समस्या तब उत्पन्न हुई जब वे तेल के लिएबोर करने के लिएआगे बढ़े, लेकिनकंटेनर कंटेनर तक पहुंचने से पहले, अपीलकर्ता ने यह कहते हुए किउनके काम से उसकी गैस निकल जाएगी, चाहे वह मुफ्त में हो या समाधान में, एक अंतरिम निषेधाज्ञा के लिएआवेदन कियाऔर प्राप्त किया, जो उन्हें चैम्बर चैम्बर में घुसने से रोकती थी। उसी समय, उन्होंने एक घोषणा करते हुए एक कार्रवाई की किवह अपनी भूमिके के भीतर प्राकृतिक गैस का मालिकहै। यह निर्णय लियागया कियद्यपिदूसरे प्रतिवादी को पट्टे में दिए गए पेट्रोलियम पर काम करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार था जो मूल हस्तांतरण में था, ऐसे खंड की अनुपस्थिति ने प्रतिवादी की शक्तियों को निरस्त या सीमितनहीं किया।दूसरे प्रतिवादी के पास पेट्रोलियमका प्रत्यक्ष अनुदान था, जबकिअपीलकर्ता के पास केवल ऐसे अवशिष्टअधिकारथे जो उत्तरदाताओं को अनुदान के के अधीन थे और यह माना गया किउत्तरदाताओं पर परिणामस्वरूप इनकार के साथ अपीलकर्ता की भूमिके भीतर मुफ्त गैस को संरक्षितकरने का कोई दायित्व नहीं था। सामान्य तरीके से पेट्रोलियमकी वसूली करने का का उनका अधिकार।

उस मामले में, सवाल यह था किक्या पट्टाधारक को पृथ्वी की परत में अंतर्निहित प्राकृतिक गैस को नुकसान पहुंचाए बिना पेट्रोलियमनिकालने का अधिकारथा। यह प्रश्न पट्टा-धारक द्वारा प्राप्त परिवहन की प्रकृति

पट्टा-धारक को दिए गए विशिष्टपट्टे के कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए बोरिस के मामले *(सुप्रा)* में निर्णय से कोई सहायता नहीं मिलतीहै।

हमारे सामने उत्पादित सभी सामग्रियांकेवल यह दिखाएंगी किप्राकृतिक गैस एक पेट्रोलियमउत्पाद है। यह भी भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है किपेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पादों के क्षेत्र को कवर करने वाले विभिन्नकानूनों कानूनों में, या तो 'पेट्रोलियमया 'पेट्रोलियमउत्पाद'शब्द को समावेशी तरीके से परिभाषितकियागया है, ताकि ताकिप्राकृतिक गैस को भी शामिलकियाजा सके। एनसाइक्लोपीडियाब्रिटानिका में, *15*वां संस्करण। वॉल्यूम. वॉल्यूम. *19,* पृष्ठ *589 (1990),* यह कहा गया है कि"तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन प्रकृति में इतने घनिष्ठ से जुड़े हुए हैं किदोनों का संदर्भ देते समय 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस'अभिव्यक्ति को छोटा करके 'पेट्रोलियमकरने की प्रथा बन गई है।"पेट्रोलियमशब्द का शाब्दिक अर्थ 'चट्टान का तेलहै। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द पेट्रा-ओलियमसे हुई है। *(*पेट्रा-अर्थात् चट्टान या पत्थर और ओलियम-अर्थात् तेल*)*। इस प्रकार, प्राकृतिक गैस को 'पेट्रोलियमया 'पेट्रोलियमउत्पाद'अभिव्यक्तिके अंतर्गत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मद्रास राज्य बनाम गैनन डंकरले एंड कंपनी , *[1959]* एससीआर *379* में, यह देखा गया किसंविधानमें प्रयुक्त विभिन्नशब्दों की व्याख्या करने में विधायीअभ्यास पर विचारकरना महत्वपूर्ण है। वेंकटराम अय्यर, जे. ने पीठ की ओर से अवधारित कियाकि

"क्रॉफ्ट बनाम डम्फी, *(1933)* एसी *156* में, संविधानमें शब्दों की व्याख्या करने में विधायीअभ्यास से जुड़े महत्व के सवाल की ओर मुड़ते हुए, सवाल यह था किकनाडाई क़ानून में कुछ प्रावधानों की वैधता क्या है, जो प्रादेशिकजल से परे जहाजों की खोज के लिएप्रावधा ानित करता है। ये प्रावधान एक सीमा शुल्क क़ानून में थे, थे, और इसका उद्देश्य तस्करों द्वारा इसके प्रावधानों की चोरी को रोकना था। इन प्रावधानों की वैधता की करते हुए, लॉर्ड मैकमिलनने सीमा शुल्क से संबंधितविधायीअभ्यास का उल्लेख किया, और देखा *:*

"जब किसीविशेषविषयपर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो शक्ति के दायरे को निर्धारित करने में यह महत्वपूर्ण है किविधायीअभ्यास में और विशेषरूप से राज्य के विधायीअभ्यास में उस विषयके भीतर भीतर क्या माना जाता है, जिसने शक्ति प्रदान की है।"

वालेस ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेडबनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटीऔर बॉम्बे उपनगरीय जिले में, लॉर्ड उथवाट ने कहा*:*

"जहां संसद ने किसी विशेष विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है*:* यूनाइटेड किंगडम के विधायी अभ्यास में उस विषयके भीतर आम तौर पर जो माना जाता है उसके संबंध में शक्ति के दायरे और अर्थ को निर्धारित करने में यह स्वीकार्य और महत्वपूर्ण है। सन्दर्भ का उद्देश्य सशक्त रूप से उस पैटर्न की तलाश नहीं है जिसके अनुरूप शक्ति का उचितप्रयोग कियाजाना चाहिए। उद्देश्य सक्षम अधिनियममें शब्दों में शामिलसामान्य अवधारणा का पता लगाना है।"

इस विषयपर विभिन्नकानूनों के सर्वेक्षण से पता चलेगा कि'पेट्रोलियमया 'पेट्रोलियमउत्पाद'शब्द को प्राकृतिक प्राकृतिक गैस और अन्य समान उत्पादों को शामिलकरने के लिएव्यापक अर्थ दिया गया है।

यूनाइटेड किंगडमके पाइपलाइन अधिनियम, *1962* में 'पेट्रोलियमको इस प्रकार परिभाषितकियागया है*:*

*"*पेट्रोलियममें कोई भी खनिज तेल या सापेक्ष हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस शामिलहै जो परतों में अपनी प्राकृतिक स्थिति में मौजूद है, चाहे इसका कोई प्रसंस्करण हुआ हो या नहीं*;* लेकिनइसमें कोयला या बिटुमिनस बिटुमिनसशेल्स या अन्य स्तरीकृत जमा शामिलनहीं हैं जिनसे विनाशकारीआसवन द्वारा तेल निकाला जा सकता है ।*"*

पेट्रोलियमको विभिन्नअधिनियमोंमें विभिन्नप्रकार से परिभाषितकियागया है, जैसा किनीचे दिया गया है*:* है*:*

पेट्रोलियम*(*उत्पादन*)* अधिनियम, *1934 (*यूके*) "*पेट्रोलियममें कोई भी खनिज तेल या सापेक्ष हाइड्रो-कार्बन और और प्राकृतिक गैस शामिलहै जो परतों में अपनी प्राकृतिक स्थिति में मौजूद है, लेकिनइसमें कोयला या बिटुमिनसशेल्स या अन्य शेल्स या अन्य स्तरीकृत जमा शामिलनहीं हैं जिनसे तेल विनाशकारीआसवन द्वारा निकाला जा सकता है।*"*

पेट्रोलियमअधिनियम, *2000 (*धारा *4)*। ऑस्ट्रेलिया*"*पेट्रोलियम*'*का अर्थ है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसमें गैसीय, तरल या ठोस अवस्था में हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रणहोता है, लेकिन इसमें कोयला या शेल शामिलनहीं होता है जब तक कियह उन परिस्थितियों में न हो जिसमें कोयला सीम मीथेन उत्पादन या सीटू गैसीकरण के लिएतकनीकों का उपयोग कियाजाना उचितहोगा।*"*

तरल ईंधन आपातकालीन अधिनियम, *1984 (*धारा *3) "*पेट्रोलियम*'*का अर्थ है*:*

एक। कोई प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, चाहे वह गैसीय, तरल या या ठोस अवस्था में हो*;* या बी. हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन और किसीअन्य पदार्थ या अन्य पदार्थों का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्रण, चाहे वह गैसीय, तरल या ठोस अवस्था में हो।

भारतीय संसद द्वारा पारित विभिन्नकानून और संबंधितनियम यह भी दर्शितकरते हैं कि'प्राकृतिक गैस'को खनिज तेल संसाधन या पेट्रोलियमउत्पाद के रूप में माना जाता था।

1. तेल क्षेत्र *(*विनियमनऔर विकास*)* अधिनियम, *1948*
*3(*सी*) "*खनिज तेल*"*में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियमशामिलहैं।

2. खान अधिनियम, *1952*
*2 (*जेजे*) "*खनिज*"*का अर्थ है वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी से खनन, खुदाई, ड्रिलिंग़ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग़उत्खनन उत्खनन या किसीअन्य ऑपरेशन द्वारा प्राप्त किएजा सकते हैं और इसमें खनिज तेल *(*जिसमें प्राकृतिक और पेट्रोलियम*)"*
शामिलहै।
3. खान और खनिज *(*विकासऔर विनियमन*)* अधिनियम, *1957*

*3. (*बी*)* "खनिज तेल"में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियमशामिलहैं।

4. पेट्रोलियमऔर प्राकृतिक गैस सवारी*, 1959*
*3 (*के*)* "पेट्रोलियम"का अर्थ है प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, चाहे प्राकृतिक गैस के रूप में या तरल चिपचिपाया ठोस रूप में, लेकिनइसमें हीलियम, जो पेट्रोलियम, या कोयला, या शैल के के संयोग में हो या कोई भी पदार्थ जो कोयला, शेल, या अन्य चट्टान से गर्मी के प्रयोग से या रासायनिक प्रक्रियाद्वारा निकाला जा सकता है।"शामिलनहीं है।

*3(*एन*)* "पेट्रोलियमउत्पाद"का अर्थ पेट्रोलियमया प्राकृतिक गैस से बनी कोई भी वस्तु है और इसमें परिष्कृत कच्चा तेल, संसाधितकच्चा पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियमसे अवशेष, क्रैकिंगस्टॉक, अनक्रैक्ड ईंधन तेल, ईंधन ईंधन तेल, उपचारित कच्चे तेल के अवशेष, आवरण शीर्ष शामिलहोंगे। गैसोलीन, प्राकृतिक गैस गैसोलीन, नेफ्था, डिस्टिलेट, गैसोलीन, मिट्टीका तेल, अपशिष्टतेल, मिश्रितगैसोलीन, चिकनाईवाला तेल, एक या अधिक अधिकतरल उत्पादों या तेल संघनन, गैस या पेट्रोलियमहाइड्रोकार्बन से प्राप्त उप-उत्पादों के साथ तेल का मिश्रणया मिश्रण, चाहे यहाँ हो गणना की गई या नहीं।"

5. पेट्रोलियमऔर खनिज पाइपलाइन *(* भूमिमें उपयोगकर्ता के अधिकारका अधिग्रहण*)* अधिनियम*, 1962*

*2. (*सी*)* "पेट्रोलियम"का वही अर्थ है जो पेट्रोलियमअधिनियम*, 1934* में है, और इसमें प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी गैस शामिलहै।"

6. तेल उद्योग *(*विकास*)* अधिनियम*, 1974*

*2. (*ज*)*। "खनिज तेल"में पेट्रोलियमऔर प्राकृतिक गैस शामिलहैं। तेल, ईंधन तेल, उपचारित कच्चा तेल अवशेष, केसिंगहेड गैसोलीन, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, नेफ्था, डिस्टिलेटगैसोलीन, केरोसीन, बिटुमेन, डामर डामर और टार, अपशिष्टतेल, मिश्रितगैसोलीन, चिकनाईवाला तेल, एक या अधिकके साथ तेल का मिश्रणया या मिश्रणतरल उत्पाद या तेल या गैस से प्राप्त उत्पाद और दो या दो से अधिकतरल उत्पादों का मिश्रणया मिश्रणया तेल संघनन और गैस या पेट्रोलियमहाइड्रोकार्बन से प्राप्त उप-उत्पाद जो यहां पहले निर्दिष्ट नहीं

सूची *I* की प्रविष्टि*53* के तहत, संसद को तेल क्षेत्रों, खनिज तेल संसाधनों के विनियमनऔर विकासके लिए कानून बनाने की शक्ति मिलीहै*;* पेट्रोलियम, पेट्रोलियमउत्पाद, अन्य तरल पदार्थ और पदार्थ संसद द्वारा कानून द्वारा खतरनाक रूप से ज्वलनशील घोषितकिएगए हैं। तेल कुओं से निकाले गए प्राकृतिक गैस उत्पाद में मुख्य रूप से मीथेन शामिलहै। प्राकृतिक गैस का उत्पादन अन्य पेट्रोलियमउत्पादों के उत्पादन से स्वतंत्र नहीं है*;* हालाँकिकुछ कुओं से केवल प्राकृतिक गैस ही निकलेगी, अन्य उत्पाद पृथ्वी के भूमिगतकक्षों से निकल सकते हैं। लेकिनसभी तेल क्षेत्रों में संभावितहाइड्रोकार्बन की खोज की जा रही है। इसलिए तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों के विनियमनमें आवश्यक रूप से विनियमनके साथ-साथ प्राकृतिक गैस का विकास विकासभी शामिलहै। देश भर में व्यापार, वाणिज्यऔर उद्योग के मुक्त और सुचारू प्रवाह के लिए प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियमउत्पाद महत्वपूर्ण भूमिकानिभाते हैं।

पुन: कावेरी जल विवादन्यायाधिकरण, *[1993]* (सप्ल.एल) एससीसी *96* में, नदियों के बहते पानी के अधिकार अधिकारको एक अधिकार'पब्लिसी ज्यूरिस', यानी जनता का अधिकारबताया गया था। इसलिएप्राकृतिक गैस गैस में पूरे देश के लोगों की हिस्सेदारी है और इसका लाभ पूरे देश को साझा करना होगा। राष्ट्रीय विकासके लिए प्राकृतिक गैस का उचित एवं उचित उपयोग होना चाहिए। यदि अकेले एक राज्य को प्राकृतिक गैस निकालने और उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो अन्य राज्य इसके न्यायसंगत हिस्से से वंचितहो जाएंगे। यह स्थिति संघ द्वारा अपनाए गए रुख को मजबूत करती है और इस निष्कर्ष का सूचक होगी कि "प्राकृतिक गैस'सूची *I* की प्रविष्टि*53* में शामिलहै। इस प्रकार, विधायीइतिहास और 'पेट्रोलियम, 'पेट्रोलियम उत्पादों'की परिभाषा 'और विभिन्नकानूनों और पुस्तकों में निहित 'खनिज तेल संसाधन'और राज्यों के बीच प्राकृतिक गैस के समान वितरणमें शामिलराष्ट्रीय हित - ये सभी कारक अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि कच्चे और तरलीकृत रूप में "प्राकृतिक गैस"पेट्रोलियमउत्पाद है और खनिज तेल संसाधन का हिस्सा, जिसे संघ द्वारा विनियमितकरने की आवश्यकता है। प्राकृतिक गैस एक पेट्रोलियमउत्पाद है, हमारा विचारहै कि प्रविष्टि*53* सूची *I* के तहत, अकेले संघ सरकार को विधायीक्षमता प्राप्त है। गुजरात अधिनियमकी धारा *2 (*जी*)* की परिभाषा के अनुसार गैस जैसा कि परिभाषितकियागया है, वह "गैस"को "गैसीय अवस्था का एक पदार्थ जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है", इसमें निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस भी शामिलहोगी। हमारा विचारहै किसातवीं अनुसूची की प्रविष्टि*25* सूची *II* के तहत, राज्य केवल गैस और गैस-कार्यों के संबंध में एक एक कानून पारित करने में सक्षम होगा और 'गैस और गैस कार्यों'शब्दों के संयोजन को ध्यान में रखते हुए, यह प्रविष्टिइसका मतलब निर्मितगैस से संबंधितकोई भी कार्य या उद्योग होगा जिसका उपयोग अक्सर औद्योगिक, चिकित्सया अन्य समान उद्देश्यों के लिएकियाजाता है। जैसा किराज्यों के लिएसुझाव दिया गया गया है, सूची *II* की प्रविष्टि*25* को समग्र रूप से पढ़ना होगा। उसमें व्यक्त भावों की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती। प्रविष्टिमें 'गैस'शब्द दूसरे शब्दों 'गैस-वर्क्स'से रंग लेगा। बैलेंटाइन्स लॉ डिक्शनरी, तीसरे संस्करण, *1969* में 'गैस वर्क्स'को "कृत्रिम गैस के निर्माण के लिएएक संयंत्र"के रूप में परिभाषितकियागया है। है। इसी तरह वेबस्टर की न्यू *20*वीं सेंचुरी डिक्शनरीमें इसे "एक प्रतिष्ठान जिसमें हीटिंग और प्रकाश के लिएगैस का निर्माण कियाजाता है"के रूप में परिभाषितकियागया है। *www.freecdictionary.com* में 'गैस 'गैस वर्क्स'को "गैस का एक कारख़ाना, सभी मशीनरी और उपकरणों के साथ; एक जगह जहां गैस उत्पन्न होती है"के रूप में समझाया गया है। 'गैस वर्क्स'शब्द का अर्थ इस अर्थ में अच्छी तरह से समझा जाता है किवह वह स्थान जहाँ गैस का निर्माण होता है। इसलिएइस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल है किसूची *II* की प्रविष्टि*25* में 'गैस'में प्राकृतिक गैस शामिलहै, जो गैस कार्यों में निर्मितगैस से मौलिकरूप से अलग है। इसलिए इसलिए सूची *II* की प्रविष्टि*25* केवल निर्मितगैस को कवर कर सकती है और इसके दायरे में प्राकृतिक गैस को को शामिल नहीं किया गया है। इससे राज्यों का यह तर्क नकारात्मक हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस से संबंधितकानून बनाने की विशेषशक्तियां केवल उनके पास हैं। सूची *II* की प्रविष्टि *25* में केवल निर्मितगैस शामिलहै। यह संविधाननिर्माताओं की स्पष्ट मंशा है। यह रीडिंगकिसीभी तरह से उस उस प्रविष्टिको 'बेकार लकड़ी'नहीं बनाएगी जैसा किराज्यों को डर था, क्योंकिप्राकृतिक गैस को उस प्रविष्टिमें शामिलकरने का कभी इरादा नहीं था। राज्यों के इस तर्क को स्वीकार करना भी मुश्किल है किसभी 'गैस'को खतरनाक रूप से ज्वलनशील के रूप में वर्गीकृत कियाजा सकता है और इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है किप्राकृतिक गैस भी राज्य सूची में शामिलहै क्योंकियह वर्गीकरण गैस की विशेषताओंपर नहीं, बल्कि इसकी उत्पत्तिके तरीके पर आधारित है। सूची *II* की प्रविष्टि*25* में निर्मितऔर गैस कार्यों में उपयोग की

की जाने वाली गैस शामिलहै। इस विशिष्टप्रविष्टि*53* के मद्देनजर, किसीभी पेट्रोलियमऔर पेट्रोलियमउत्पादों उत्पादों के लिए राज्य विधानमंडलके पास प्राकृतिक गैस के संबंध में कोई कानून पारित करने की कोई विधायी विधायीक्षमता नहीं है। उस हद तक, गुजरात अधिनियममें निहित प्रावधानों में विधायीक्षमता का अभाव है।

परिणाम में, संदर्भ का उत्तर निम्नलिखितशब्दों में दिया गया है:

प्रश्न *1.* क्या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) सहित किसीभी भौतिक रूप में प्राकृतिक गैस सूची *I* की प्रविष्टि*53* में शामिलएक संघ का विषयहै और संघ के पास अधिनियमबनाने के लिएविशेषविधायीक्षमता है। है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) सहित एआई प्राकृतिक गैस एक संघ का विषयहै जो सूची *I* की प्रविष्टि *53* में शामिलहै और संघ के पास प्राकृतिक गैस पर कानून बनाने की विशेषविधायीक्षमता है।

प्र.*2.* क्या राज्यों के पास संविधानकी सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि*25* के तहत प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के विषयपर कानून बनाने की विधायीक्षमता है।

ए.*2.* संविधानकी सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि*25* के तहत राज्यों के पास प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के विषयपर कानून बनाने की कोई विधायीक्षमता नहीं है।

प्र.*3.* क्या गुजरात राज्य के पास गुजरात गैस (पारेषण, आपूर्ति और वितरणका विनियमन) अधिनियम, *2001* *2001* को अधिनियमितकरने की विधायीक्षमता थी।

ए.*3.* गुजरात गैस (पारेषण, आपूर्ति और वितरणका विनियमन) अधिनियम, *2001,* जहां तक प्राकृतिक गैस या या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से संबंधितप्रावधानों का सवाल है, बिना किसीविधायीक्षमता के है और अधिनियमउस सीमा तक है संविधानके दायरे से बाहर.

आदेश भारत के संविधानके अनुच्छेद *143(1)* के तहत विशेषसंदर्भ संख्या *1/2001* में दी गई राय के आलोक में में , रिट याचिकाऔर सिविलअपील खारिज की जाती है।

प्रश्नों/याचिकाका उत्तर दिया और अपीलें खारिज की जाती हैं।